भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 642
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025

दूरसंचार क्षेत्र में की गई पहल

642. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में डिजिटल संपर्क बढ़ाने के लिए भारतनेट परियोजना को तीव्र गति से लागू किया है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों और जिलों के विकासशील क्षेत्रों में विशेष रूप से 5जी सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग द्वारा बैंकिंग, बीमा और ई-कॉमर्स सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई नई पहल की गई है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्पेक्ट्रम आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई तकनीकी सुधार किए गए हैं और यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में घरेलू निर्माण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना प्रारंभ की है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है, अब तक 2,14,325 जीपी को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।

(ख) 5जी सेवाओं के रोल आउट को सक्षम बनाने के लिए, वर्ष 2022 और 2024 में आयोजित स्पेक्ट्रम नीलामी के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को 700 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड सहित अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंडों में स्पेक्ट्रम का एक्सेस सौंपा गया है। नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले सफल बोलीदाताओं को 5जी सहित किसी भी आईएमटी प्रौद्योगिकी को संस्थापित करने की अनुमति है।

(ग) डाक विभाग ने डाकघर बचत बैंक सेवाओं के डिजिटलीकरण, डाक जीवन बीमा को कागज रहित और ऑनलाइन प्रणाली में परिवर्तित करने, डाक घर निर्यात केंद्रों की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, बीमा और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ई-कॉमर्स संस्थाओं के साथ सहयोग जैसी नई पहल शुरू की है।

(घ) स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी और भेदभाव रहित है, जिसकी शुरुआत सार्वजनिक रूप से साझा किए गए आवेदन आमंत्रण नोटिस (एनआईए) से होती है जिसमें नियमों, समय सीमा और पात्रता का विवरण होता है। नीलामी को एक सुरक्षित, मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) द्वारा ऑडिट की गई इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाता है।

(ङ) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने संचार क्षेत्र में नवाचार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। 'डिजिटल कम्युनिकेशंस इनोवेशन स्क्वायर (डीसीआईएस)' स्कीम के तहत दूरसंचार विभाग ने स्वदेशी 5जी सहित उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹108 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के साथ स्टार्ट-अप और एमएसएमई द्वारा चलाए जा रहे 126 परियोजनाओं को सहायता दी है।

इसके अतिरिक्त, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम जिसे दिनांक 24.02.2021 को अधिसूचित किया गया और जो अप्रैल 2021 से प्रभावी है, का उद्देश्य ₹12,195 करोड़ के परिव्यय के साथ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। पीएलआई स्कीम के तहत कुल 42 कंपनियों - 28 एमएसएमई और 14 गैर-एमएसएमई - को लाभार्थी के रूप में अनुमोदित किया गया है। दिनांक 31 मई 2025 तक पीएलआई लाभार्थी कंपनियों ने सामूहिक रूप से ₹4,305 करोड़ का निवेश किया है, जिससे ₹85,391 करोड़ की बिक्री हुई है जिसमें ₹16,414 करोड़ का निर्यात शामिल है। इस निवेश के परिणामस्वरूप 28,067 व्यक्तियों को रोजगार भी मिला है।

***